RNI No. MPHIN/2015/64451 डाक पंजीयन क्र. MP/IDC/1525/2019-2021 IPT डाक द्वारा प्रेषण प्रति शुक्रवार indianplasttimes@gmail.com

www.Indianplasttimes.in

इंडियन प्लास्ट टाइम्स

■ INDORE ■ 06 JANUARY TO 12 JANUARY 2021 ■ प्रति बुधवार ■ वर्ष 06 ■ अंक 20 ■ पृष्ठ 8 ■ कीमत 5 रु.

Inside News

सऊदी अरब ने किया कच्चे तेल के उत्पादन में कटौती का वादा Page 2

जीएसटी संग्रह ने दिसंबर में बनाया रिकार्ड 1.15 लाख करोड़ रुपये पर पहुंचा Page 3

सतर्क रहते हुये 2021 के लिये वृद्धि योजनाओं पर अमल कर रहा वाहन उद्योग Page 7

editoria!

बड़ी पहल का मौका

साल 2021 की शुरुआत इस मायने में भी अहम है कि इसी 1 जनवरी से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में भारत का दो साल का कार्यकाल शुरू हो गया है। हालांकि यह इस तरह का कोई पहला मौका नहीं है। भारत इससे पहले भी सात बार सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य चुना जा चुका है। आजादी के ठीक बाद पचास के दशक से ही इसकी शुरुआत हो गई थी। पहली बार 1950-51 में दो वर्षीय कार्यकाल पूरा करने के बाद से प्रायः हर दशक में भारत को सुरक्षा परिषद की सदस्यता मिलती रही है। सत्तर के दशक में तो दो बार (72-73 और फिर 77-78) यह मौका आया। जाहिर है, सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्यता अपने आप में कोई निर्णायक बात नहीं है। खास बात उन परिस्थितियों में है जिनमें भारत को इस महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय संस्था के जरिये अपनी भूमिका निभाने का यह मौका मिल रहा है। ध्यान रहे, सुरक्षा परिषद की सदस्यता में क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व का भी ध्यान रखा जाता है, लेकिन उसके लिए बाकायदा चुनाव होता है और किसी भी देश के चुने जाने के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा में दो तिहाई बहुमत जरूरी होता है। भारत को इस बार 193 सदस्यीय महासभा में 184 वोट मिले थे। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि भारत की सुरक्षा परिषद सदस्यता से दुनिया की कितनी उम्मीदें जुड़ी हैं। यह दौर है भी ऐसा जिसमें कोरोना महामारी और अर्थव्यवस्था की तबाही ने पूरी दुनिया को बेहाल कर रखा है। इसके अलावा आतंकवाद जैसी पुरानी समस्या तो संयुक्त राष्ट्र का सिरदर्द बनी ही हुई है, हाल के दिनों में बढ़ती राष्ट्रवादी आक्रामकता भी अंतरराष्ट्रीयता की भावना के लिए खासी नुकसानदेह साबित हो रही है। अमेरिका समेत विभिन्न देशों के संकीर्ण रवैये से संयुक्त राष्ट्र जैसी अंतरराष्ट्रीय संस्था के लिए गुंजाइश लगातार कम हुई है। ऐसे में एक परिपक्व लोकतंत्र के नाते भारत सुरक्षा परिषद में अपनी सकारात्मक भूमिका के जरिए बहुपक्षीयता को बढ़ावा देते हुए संयुक्त राष्ट्र की प्रासंगिकता नए सिरे से स्थापित करने में मददगार हो सकता है। भारत सुरक्षा परिषद का ऐसा एकमात्र सदस्य होगा जो इस समय खुद दो-दो अंतरराष्ट्रीय सीमाओं पर फौजों के जमावड़े से घिरा है। यह जहां उसकी स्थिति की जटिलता को बढ़ाता है, वहीं विभिन्न अंतरराष्ट्रीय विवादों को शांति और सामंजस्यपूर्ण बातचीत से सुलझाने की उसकी कोशिशों को ज्यादा जेनुइन भी बनाता है। ध्यान रहे, भारत इधर काफी समय से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता का विस्तार करने की मांग के साथ उसके लिए अपनी दावेदारी जताता रहा है। कई अन्य देश उसका समर्थन भी करते रहे हैं। दो वर्षों का यह कार्यकाल इस लिहाज से अहम है कि इस दौरान अगर भारत सुरक्षा परिषद के जरिये प्रमुख प्रश्नों पर सार्थक पहलकदमी ले सका तो न केवल दुनिया को इस कठिन दौर से निकलने में आसानी होगी, बल्कि स्थायी सदस्यता का भारतीय दावा भी और पुख्ता होगा।

पहली छमाही में डिमांड कम रहने की आशंका

OPEC का ओपिनियन

नई दिल्ली। एजेंसी

कोरोना वायरस (Covid-19) महामारी अभी टली नहीं है. इसलिए इसका असर भी नए साल में क्रूड ऑयल (Crude oil) में देखने को मिलने वाला है. ब्रिटेन में आए कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन ने पूरी दुनिया को अलर्ट कर दिया है. यही वजह है कि नए साल के पहले कारोबारी दिन क्रूड ऑयल (कच्चा तेल) की कीमत धराशाई हो गई. पेट्रोलियम एक्सपोर्ट्स देशों के प्रमुख संगठन ओपेक (OPEC) ने नए साल की पहली छमाही में क्रूड ऑयल की डिमांड कम रहने की आशंका जताई है. इसका असर पहले ही दिन कच्चा तेल पर देखा गया. रॉयटर्स की खबर के मुताबिक, ओपेक और बाकी उत्पादकों की फरवरी के लिए प्रोडक्शन लेवल पर मीटिंग से पहले तेल में नरमी देखी गई

क्रूड ऑयल का भाव

खबर के मुताबिक, मार्च के लिए ब्रेंट क्रूड 51.76 डॉलर प्रति बैरल, 4 सेंट या 0.08 प्रतिशत की गिरावट के साथ 0038 GMT था, जबकि फरवरी के लिए यूएस वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट क्रूड 9 सेंट, या 0.2 प्रतिशत गिरकर 48.43 डॉलर प्रति बैरल था. पेट्रोलियम एक्सपोर्ट्स देशों के संगठन (ओपेक) के महासचिव मोहम्मद बरकिंडो ने कहा है कि इस साल कच्चे तेल की डिमांड में 5.9 मिलियन बैरल प्रति दिन (बीपीडी) से बढ़कर 95.9 मिलियन बीपीडी होने की उम्मीद है, लेकिन साल 2021 की पहली छमाही में डिमांड में भारी गिरावट का जोखिम भी है.

2020 में कच्चे तेल की कीमत 20 प्रतिशत रही कम

बीते साल कच्चे तेल की कीमत साल 2019 के मुकाबले औसतन 20 प्रतिशत कम हो गई. इसके बाद भी हम ग्लोबल इकोनॉमिक स्लोडाउन से उबरने के लिए तेल की कीमतें कम कर दी. यहां तक कि दुनिया के प्रमुख उत्पादकों ने वर्ष के दौरान रिकॉर्ड उत्पादन कटौती पर सहमत भी हुए.

ओपेक ने लिया उत्पादन और समीक्षा का फैसला

ओपेक और उससे जुड़े उत्पादकों ने जनवरी में हर रोज 50000 बैरल प्रतिदिन उत्पादन बढ़ाने के लिए एक मीटिंग का फैसला किया और उत्पादन की समीक्षा करने के लिए हर महीने मिलने पर भी सहमति जताई. एनर्जी एस्पेक्ट्स और आरबीसी कैपिटल के विश्लेषकों ने कहा कि ओपेक फरवरी में जनवरी के उत्पादन लेवल को बनाए रखेगा. RBCCapital की हेलिमा क्रॉफ्ट ने कहा कि आने वाले समय में वैक्सीन के डेवलपमेंट के मुताबिक चीजें होंगी. संयुक्त राज्य अमेरिका में, कच्चे तेल का उत्पादन कमजोर कीमतों और कमजोर मांग के चलते कम रहा.

DRDO की बड़ी कामयाबी

इजराइल के सहयोग से सतह से हवा डिफेंस सिस्टम का सफल परीक्षण

जेरुसलम। एजेंसी

भारत और इजरायल ने सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल रक्षा प्रणाली का कामयाब परीक्षण किया है। दुश्मन देशों के हवाई हमले से निपटने के लिए संयुक्त रूप से विकसित हुए इस मिसाइल डिफेंस सिस्टम का परीक्षण पिछले हफ्ते हुआ। डीआरडीओ (DRDO) और इजराइल एयरोस्पेस इंडस्ट्रीज (IAI) की नई ईजाद अपने आप में अनूठी है। जिससे पार पाना किसी के बस की बात नहीं होगी।

इंडो-इजरायल रक्षा सहयोग का नतीजा है MRSAM

MRSAM एक ऐसा एयर और मिसाइल डिफेंस सिस्टम है जो विभिन्न प्रकार के एरियल प्लेटफार्म्स को अभेद सुरक्षा कवच प्रदान करता है। रक्षा विशेषज्ञों के मुताबिक MRSAM दुश्मन के विमानों को खुद से 50 से 70 ख्र की दूरी पर तबाह कर सकता है। इजरायल और भारत की साझेदारी में विकसित, MRSAM का उपयोग भारतीय सेना के तीनों विंग्स में होगा। इजरायल (Israel) के सुरक्षा बल भी इसका इस्तेमाल करेंगे। इसमें मौजूद हाईटेक रडार, मोबाइल लॉन्चर, इंटरसेप्टर, एडवांस आरएफ सीकर नई तकनीक से बना है। डिफेंस सिस्टम की कमांड और नियंत्रण प्रणाली भी बेहतरीन है।

डीआरडीओ के साथ काम करना गर्व की बात: IAI

इजरायल की रक्षा कंपनी IAI के सीईओ बोज लेवी के मुताबिक कोरोना काल की चुनौतियों के बीच तैयार हुआ ये MRSAM (Air & Missile Defense System) (शेष पृष्ठ 2 पर)

सऊदी अरब ने किया कच्चे तेल के उत्पादन में कटौती का वादा

11 महीने के उच्च स्तर पर पहुंचा कच्चा तेल

नई दिल्ली। एजेंसी

कच्चे तेल की कीमतें 11 माह के उच्च स्तर पर पहुंच गई हैं। फरवरी 2020 में कच्चे तेल के दाम इस स्तर पर थे। सऊदी अरब अपने साथ के उत्पादकों के साथ एक बैठक में उम्मीद से अधिक उत्पादन घटाने के लिए तैयार होने के बाद तेल की कीमतें बुधवार को फरवरी 2020 के बाद से उच्चतम स्तर पर पहुंच गईं, जबकि उद्योग के आंकड़ों से पता चलता है कि पिछले सप्ताह अमेरिकी कच्चे तेल के स्टॉक में गिरावट दर्ज की गई थी।

26 फरवरी, 2020 के बाद ब्रेंट क्रूड लगभग 1 फीसदी की तेजी के साथ 54.09 डॉलर प्रति बैरल हो गया था। मंगलवार को 4.9 फीसदी की छलांग लगाने के बाद यह 0536 उश्ऊ पर 53.87 डॉलर प्रति बैरल पर था। यूएस वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट (WTI) वायदा 50.24 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गया। 26 फरवरी 2020 को यह फिसलकर 50 डॉलर प्रति बैरल पर था। मंगलवार को डब्लूटीआई क्रूड में 4.6 फीसदी की तेजी देखी गई थी।

पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन (OPEC) और दुनिया के सबसेप्रमुख निर्माता जो समूह को OPEC + के नाम से जानते हैं और अन्य के साथ बैठक के बाद, बड़े तेल निर्यातक, सऊदी अरब ने फरवरी और मार्च में 1 मिलियन बैरल प्रति दिन (बीपीडी) के अतिरिक्त, स्वैच्छिक तेल उत्पादन में कटौती करने के लिए मंगलवार को सहमति व्यक्त की। सऊदी अरब द्वारा सहमत कटौती को अन्य उत्पादकों को ओपेक + समूह में उत्पादन स्थिर रखने के लिए राजी करने के लिए एक सौदे में शामिल किया गया था।

दुनिया के कई हिस्सों में कोरोनोवायरस संक्रमण तेजी से फैल रहा है, तेल उत्पादक देश कीमतों का समर्थन करने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि नए लॉकडाउन से मांग प्रभावित हो रही है। गोल्डमैन सैक्स ने एक नोट में कहा, 'इस तेजी से आपूर्ति समझौते के बावजूद, हम मानते हैं कि सऊदी के निर्णय की संभावना है कि लॉकडाउन वापसी के रूप में कमजोर मांग के संकेत को दर्शाता है,' हालांकि, निवेश बैंक ने ब्रेंट के लिए 65 डॉलर प्रति बैरल के लिए वर्ष के अंत में अपने 2021 पूर्वानुमान बनाए रखा। गौरतलब है कि ओपेक के सदस्य ईरान ने सोमवार को खाड़ी में एक दक्षिण कोरियाई टैंकर को जब्त कर लिया और कीमतों का समर्थन करना जारी रखा। तेहरान ने इस बात से इनकार किया कि अमेरिकी प्रतिबंधों के तहत जमे हुए 7 बिलियन डॉलर के फंड को रिहा करने के लिए सोल को धक्का देते हुए टैंकर को जब्त करने के बाद जहाज और उसके चालक दल को बंधक बना लिया गया था। इस बीच अमेरिकी कच्चे तेल का भंडार सप्ताह में 1.7 मिलियन बैरल घटकर 1 जनवरी से 491.3 मिलियन बैरल हो गया है।

पेट्रोल के रेट में रिकॉर्ड बढ़ोतरी के लिए रहें तैयार

कच्चे तेल के भाव में बड़ी तेजी

नई दिल्ली। एजेंसी

पेट्रोल की कीमतें एक बार फिर नई ऊंचाई पर पहुंच सकती हैं। राजधानी दिल्ली में ही बुधवार को पेट्रोल का भाव 83।97 रुपये प्रति लीटर पर पहुंच गया है। लगातार 29 दिनों तक स्थिर रहने के बाद बुधवार को पेट्रोल के भाव में 26 पैसे प्रति लीटर का इजाफा हुआ है, जबकि डीजल भी 25 पैसे तक महंगा हुआ है। राष्ट्रीय राजधानी में आज एक लीटर डीज़ल का भाव 74।12 रुपये है। दरअसल, कोरोना वायरस महामारी ने वैश्विक स्तर पर एनर्जी डिमांड को प्रभावित किया है। कई देशों में वैक्सीनेशन शुरू होने की वजह से अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल (Crude Oil) का भाव चढ़ा है। ब्रेंट क्रूड ऑयल 53।86 डॉलर प्रति बैरल और वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट (WTI) 50 डॉलर के करीब ट्रेड कर रहा है।

अंतिम बार कब रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचा था पेट्रोल-डीजल का भाव?

प्रति बैरल एक डॉलर के इजाफा से भारत के कच्चे तेल आयात बिल (Import Bill) पर 10,700 करोड़ रुपये सालाना का बोझ पड़ता है। लाइवमिंट की एक रिपोर्ट में सरकारी अधिकारी के हवाले से कहा गया है कि तेल कंपनियों ने पिछले कुछ समय में खुदरा दरों को स्थिर रखा है। अब कीमतें बहुत बढ़ चुकी हैं। दिल्ली में अंतिम बार पेट्रोल का उच्चतम भाव 4 अक्टूबर 2018 को 84 रुपये प्रति लीटर पर था। जबकि, पिछले साल ही डीजल का भाव 81।94 रुपये प्रति लीटर के साथ उच्चतम स्तर पर पहुंचा था। देश में ट्रांसपोर्टेशन और ईंधन की दरों में लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है। इससे सरकार पर टैक्स दरें कम करने का भी दबाव बढ़ा है। बता दें कि रिफाइनरी प्राइस के अलावा ईंधन पर केंद्र सरकार और राज्य सरकारों द्वारा लगाया जाने वाला टैक्स और डीलर्स कमिशन भी ईंधन के दाम में जोड़ा जाता है।

ओपेक देशों ने कच्चे तेल का उत्पादन कम करने का फैसला लिया

बुधवार को कीमतों में यह तेजी पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग देशों (OPEC) प्लस की बैठक के बाद आया है। इस बैठक में फरवरी और मार्च 2021 के लिए उत्पादन को लेकर फैसला लिया गया है। दिसंबर में ओपेक प्लस ने निर्णय किया था कि जनवरी से प्रति दिन 5 लाख बैरल कच्चे तेल का उत्पादन कम किया जाएगा। ओपेक ने अपने बयान में कहा है, 'बैठक में फैसला लिया गया कि उत्पादन को धीरे-धीरे 2 mb/d पर ले जाना है। मार्केट की स्थिति के आधार पर इसकी गति तय की जाएगी।'

भारत के लिए क्या है ओपेक के इस फैसले का मतलब?

भारत के लिए ओपेक प्लस का यह फैसला मायने रखता है, क्योंकि वैश्विक तेल उत्पादन में ओपेक की हिस्सेदारी 40 फीसदी तक है। भारत अपनी जरूरत का 83 फीसदी कच्चा तेल ओपेक देशों से ही आयात करता है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दौर से फायदा मिला है। भारत ने अपने रणनीतिक ऑयल रिज़र्व (Strategic Oil Reserve) को भरने के लिए औसतन 19 डॉलर प्रति बैरल की दर पर कच्चे तेल की खरीद की है।

कमजोर मांग और रिफाइनिंग मार्जिन को लेकर सतर्क हैं ओपेक देश

ओपेक ने अपनी बैठक में इस बात पर चर्चा किया कि कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामले, सख्त लॉकडाउन का दौर और अर्थव्यवस्था को लेकर अनिश्चितता का दौर 2021 में भी देखने को मिलेगा। हालांकि, बैठक में इस बात पर चर्चा हुई की वैक्सीन डेवलपमेंट को लेकर आ रही खबरों की वजह से मार्केट में उत्साह भी देखने के मिला है। लेकिन, इन सबके बीच कमजोर मांग और कम रिफाइनिंग मार्जिन को देखते हुए सतर्क रहने की जरूरत है।

आयात बिल कम करने के लिए क्या कर रहा भारत?

भारत पूरी दुनिया में कच्चे तेल का तीसरा सबसे बड़ा आयातक देश है। केंद्र सरकार अब सरकारी और प्राइवेट सेक्टर की तेल रिफाइनिंग कंपनियों के साथ सहयोगी रूप से कच्चे तेल आयात करने का विकल्प तलाश रही है। पब्लिक और प्राइवेट फर्म्स द्वारा अपने आप में इस पहले कदम से न केवल आयात बिल को कम करने में मदद मिलेगी, बल्कि चीन को काउंटर करने में भी मदद मिलेगी। दूसरा सबसे बड़ा आयातक होने की वजह से चीन को बेहतर टर्म्स पर तेल आयात करने का मौका मिलता है। भारत के लिए समस्या है कि वैश्विक बाजार में कच्चे तेल के इजाफे का सीधा असर आयात बिल पर पड़ता है। साथ ही इससे महंगाई और व्यापार घाटा भी बढ़ता है। वित्त वर्ष 2019-21 में भान ने कच्चे तेल के आयात पर 101.4 अरब डॉलर खर्च किया था। वित्त वर्ष 2018-19 में यह 111.9 अरब डॉलर था।

इजराइल के सहयोग से सतह से हवा डिफेंस सिस्टम का सफल परीक्षण

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

डिफेंस सिस्टम आज के दौर की चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। लेवी ने कहा, 'ट्रायल में मिली ये कामयाबी बेहद महत्वपूर्ण है। वहीं डीआरडीओ के साथ काम करना हमारे लिए गर्व की बात है। कामयाबी के इस रास्ते पर हम आगे भी साथ चलने पर प्रतिबद्ध हैं।

इजरायल के रक्षा उत्पादों की दीवानी है दुनिया

इजरायली रक्षा उद्योग की ओर से आई प्रतिक्रिया के मुताबिक, 'हमारे एक्सपर्ट्स और भारतीय वैज्ञानिकों की मौजूदगी में हुआ परीक्षण कामयाब रहा। इस दौरान हमने उड़ान परीक्षण के विभिन्न संदर्भों का बारीक आंकलन किया। जो हर मानक पर कामयाब रहा. इजरायल के सहयोग से बने और भारत के सुरक्षा बेड़े में इस ब्रह्मास्त्र का वार अचूक है। इस नए रक्षा कवच को नापाक हरकतों को अंजाम देने वाले दुश्मनों के लिए एक झटका माना जा रहा है।

एलएंडटी हाइड्रोकार्बन को एचपीसीएल राजस्थान रिफाइनरी से मिला सात हजार करोड़ रुपये से अधिक का ठेका

नयी दिल्ली। एजेंसी

एलएंडटी हाइड्रोकार्बन इंजीनियरिंग (एलटीएचई) ने सोमवार को कहा कि उसे एचपीसीएल राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड (एचआरआरएल) से सात हजार करोड़ रुपये से अधिक का ठेका मिला है। एलटीएचई निर्माण कंपनी लार्सन एंड टुब्रो (एलएंडटी) की पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी है। एचआरआरएल हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन (एचपीसीएल) और राजस्थान सरकार का संयुक्त उपक्रम है। एलएंडटी ने शेयर बाजारों को बताया कि उसकी अनुषंगी को यह ठेका दोहरी फीड क्रैकर इकाई बनाने के लिये मिला है। हालांकि कंपनी ने यह नहीं बताया कि यह ठेका कितनी राशि का है। कंपनी ने कहा कि यह मेगा प्रोजेक्ट है। सामान्यतः सात हजार करोड़ रुपये से अधिक की परियोजनाओं को मेगा प्रोजेक्ट कहा जाता है। एलएंडटी का शेयर बीएसई पर 1.24 प्रतिशत की बढ़त के साथ 1161.95 रुपये पर कारोबार कर रहा था।

जीएसटी संग्रह ने दिसंबर में बनाया रिकार्ड 1.15 लाख करोड़ रुपये पर पहुंचा

नयी दिल्ली। एजेंसी

माल एवं सेवा कर (जीएसटी) संग्रह ने दिसंबर में नया रिकार्ड बनाया है। दिसंबर में यह 1.15 लाख करोड़ रुपये रहा है जो कि किसी एक महीने में अब तक का सर्वोच्च संग्रह रहा है। 'लॉकडाउन' से जुड़ी पाबंदियों में ढील दिये जाने के साथ आर्थिक गतिविधियां बढ़ने से जीएसटी संग्रह बढ़ा है। दिसंबर 2020 का यह जीएसटी संग्रह एक साल पहले के दिसंबर के मुकाबले 12 प्रतिशत अधिक है। देश में माल एवं सेवाओं की बिक्री के समय उसपर जीएसटी वसूला जाता है। खाने -पीने का सामान हो, यात्रा बुकिंग हो या फिर बीमा प्रीमियम का भुगतान ऐसे सामान अथवा सेवाओं पर जीएसटी लगाया जाता है। वित्त मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि दिसंबर 2020 में सकल जीएसटी राजस्व 1,15,174 करोड़ रुपये रहा। यह इससे पिछले महीने के संग्रह के मुकाबले 10 प्रतिशत अधिक है। यह पिछले 21 महीनों में सबसे अधिक मासिक राजस्व वृद्धि है। वित्त मंत्रालय ने बयान में कहा कि देश में जुलाई 2017 से जीएसटी के अमल में आने के बाद दिसंबर में प्राप्त जीएसटी सर्वाधिक रहा है। इससे पहले अप्रैल 2019 में 1,13,866 करोड़ रुपये का सर्वाधिक जीएसटी संग्रह हुआ था। यह लगातार तीसरा महीना है जब जीएसटी संग्रह एक लाख करोड़ रुपये से अधिक रहा है। साथ ही यह चौथा लगातार महीना है जब जीएसटी संग्रह 2019 के इन्हीं महीनों के मुकाबले बेहतर रहा है। बयान के अनुसार यह महामारी के बाद तेज आर्थिक सुधार और जीएसटी चोरी और फर्जी बिल के खिलाफ चलाए गए देशव्यापी अभियान और व्यवस्थागत बदलावों के चलते संभव हुआ। इन सबके कारण अनुपालन में सुधार हुआ है। सरकार ने 2020 में कोरोना वायरस महामारी की रोकथाम के लिये 25 मार्च से देशव्यापी 'लॉकडाउन' लगाये जाने की घोषणा की थी। इससे मांग कम होने तथा ज्यादातर कंपनियों में कामकाज बंद होने से अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल असर पड़ा। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में आर्थिक वृद्धि में अब तक की सबसे बड़ी 23.9 प्रतिशत की गिरावट आयी। 'लॉकडाउन' पाबंदियों में धीरे-धीरे ढील दिये जाने के बाद से अर्थव्यवस्था के कई हिस्सों में तेजी आयी।

पहले चरण में प्राथमिकता वाले समूहों के टीकाकरण के लिये टीके का पर्याप्त भंडारः नीति आयोग

नयी दिल्ली। एजेंसी

नीति आयोग के सदस्य वीके पॉल ने सोमवार को कहा कि स्वास्थ्यकर्मियों समेत कोरोना महामारी से अग्रिम मोर्चे पर जूझ रहे लोगों का पहले चरण में टीकाकरण करने के लिये देश में टीके का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है। पॉल कोविड-19 के टीकाकरण को लेकर बने राष्ट्रीय विशेषज्ञ समूह के चेयरमैन भी हैं। उन्होंने कहा कि सरकार शीघ्र ही टीके की खरीद व उसके वितरण की अपनी योजना का खुलासा करेगी। पॉल ने पीटीआई-भाषा से एक साक्षात्कार में कहा, "हमारे पहले चरण में प्राथमिकता वाले समूह को टीका मिलेगा, जिसमें मृत्यु दर के उच्च जोखिम वाले लोग और हमारे स्वास्थ्य सेवा व अग्रिम पंक्ति के कर्मी शामिल हैं। हमारा मानना है कि हमारे पास उनके लिये पर्याप्त भंडार है।" भारत के औषधि नियामक डीसीजीआई ने दो टीकों के सीमित आपात उपयोग को रविवार को मंजूरी दी है। भारत के औषध महानियंत्रक ने जिन दो टीकों के

सीमित आपात उपयोग की मंजूरी दी है, उनमें ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय और एस्ट्राजेनेका के द्वारा सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के साथ मिलकर तैयार कोविशील्ड तथा घरेलू दवा कंपनी भारत बायोटेकके द्वारा विकसित पूर्णतः स्वदेशी कोवैक्सीन शामिल है। पॉल ने कहा कि अब से तीन से चार महीने बाद अन्य टीके भी उपलब्ध होंगे और तब भंडार भी बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि तब टीकाकरण कार्यक्रम में अधिक तेजी लायी जा सकती है। यह पूछे जाने पर कि सरकार कोविड-19 टीके की खरीद और वितरण के लिये अपनी योजनाओं की घोषणा कब करेगी, उन्होंने कहा, "यह अब किया जायेगा। अब आवश्यक कदम उठाये जा चुके हैं, अब बाकी सभी कदम उठाये जायेंगे।" यह पूछे जाने पर कि कोविड -19 के सामूहिक टीकाकरण में सबसे बड़ी चुनौती क्या होगी, पॉल ने कहा कि इस तरह के प्रयास के लिये सबसे बड़ी चुनौती एक साथ लोगों को जुटाना है। उन्होंने कहा, "इस तरह के पैमाने पर सामूहिक टीकाकरण के लिये सबसे महत्वपूर्ण चुनौती नियत दिन पर लाभार्थियों को जुटाना और समस्त सावधानियों का पालन करते हुए सुगमता से टीकाकरण पूरा करना है।" पॉल के अनुसार, टीकाकरण का उद्देश्य बंटा हुआ और पदानुक्रमित है। उन्होंने कहा, 'आखिरकार, हम महामारी को रोकने के लिये टीकाकरण करना चाहते हैं। यही अंतिम उद्देश्य है।" उन्होंने कहा कि इसे हासिल करने के लिये टीकाकरण के माध्यम से लगभग 70 प्रतिशत सामुहिक प्रतिरक्षा हासिल की जानी चाहिये। यह या तो टीकाकरण के माध्यम से हो या स्वतः महामारी से संक्रमित होकर हो। पॉल ने बताया कि सामान्य जीवन चलाते रहने के लिये पर्याप्त टीकाप्राप्त लोग होने चाहिये, ताकि देश का उद्योग, स्कूल, परिवहन, न्यायिक प्रणाली और संसदीय गतिविधि आगे बढ़ती रहे।

बैंक ऑफ बड़ौदा ने व्हॉट्सएप बैंकिंग सेवाएं शुरू कीं

मुंबई। एजेंसी

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ऑफ बड़ौदा (बॉब) ने मैसेजिंग मंच व्हॉट्सएप पर बैंकिंग सेवाएं शुरू करने की घोषणा की है। बैंक ऑफ बड़ौदा व्हॉट्सएप के जरिये खाते में बैलेंस की जानकारी, मिनी स्टेटमेंट, चेक की स्थिति जानकारी, चेकबुक आग्रह, डेबिट कॉर्ड को ब्लॉक करने और उत्पाद एवं सेवाओं के बारे सूचना जैसी सेवाएं उपलब्ध करा रहा है। बैंक के कार्यकारी निदेशक ए के खुराना ने बयान में कहा, "सोशल मीडिया के बढ़ते प्रभाव के बीच हमारा मानना है कि व्हॉट्सएप बैंकिंग के जरिये ग्राहकों को काफी सुविधा मिलेगी और वे अपनी बैंकिंग जरूरतों को पूरा कर पाएंगे।" मैसेजिंग मंच के जरिये बैंकिंग सेवाएं चौबीसों घंटे सातों दिन उपलब्ध होंगी। इसके लिए अतिरिक्त ऐप्लिकेशन डाउनलोड करने की जरूरत नहीं होगी। ऐसे लोग जो बैंक के ग्राहक नहीं हैं, वे भी मंच के जरिये बैंक के उत्पादों, सेवाओं, पेशकश, एटीएम और शाखा के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं।

चार जनवरी तक 5 करोड़ से अधिक आयकर रिटर्न भरे गये

नयी दिल्ली। एजेंसी

आयकर विभाग ने मंगलवार को कहा कि वित्त वर्ष 2019-20 के लिये चार जनवरी तक 5 करोड़ से अधिक आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल किये गये। सरकार ने लोगों के लिये आयकर रिटर्न दाखिल करने की समयसीमा बढ़ाकर 10 जनवरी और कंपनियों के लिये 15 फरवरी कर दी है। आयकर विभाग ने ट्विटर पर लिखा है, "आकलन वर्ष 2020-21 के लिये 5.01 करोड़ से अधिक आयकर रिटर्न 4 जनवरी, 2021 तक भरे जा चुके हैं।" वहीं, वित्त वर्ष 2018-19 के लिये आईटीआर भरने की समयसीमा 31 अगस्त थी और उसके लिये 5.63 करोड़ से अधिक आयकर रिटर्न जमा किये गये। आंकड़े के विश्लेषण से पता चलता है कि 2019-20 के लिये व्यक्तिगत तौर पर आयकर रिटर्न भरने की गति कुछ धीमी है जबकि कंपनियों तथा ट्रस्ट के मामले में बढ़ी है। चार जनवरी 2021 तक 2.7 करोड़ आईटीआर-1 दाखिल की गई। यह चार सितंबर 2019 तक भरी गई 3.09 करोड़ के मुकाबले कम है। वहीं चार जनवरी तक 1.04 करोड़ आईटीआर- 4 दाखिल की गई जबकि 4 सितंबर 2019 तक 1.28 करोड़ आईटीआर-4 दाखिल की गई थी।

भारत वायुसेना के लिए 56 परिवहन विमान खरीदने के लिए 2.5 अरब डॉलर के सौदा को अंतिम रूप दे सकता है

नयी दिल्ली। एजेंसी

ऐसी संभावना है कि अगले कुछ महीने में भारत वायुसेना के लिए 2.5 अरब डॉलर की लागत से 56 परिवहन विमान खरीदने के बड़े सौदे को अंतिम रूप देगा। आधिकारिक सूत्रों ने मंगलवार को यह जानकारी दी। सूत्रों ने बताया कि इस परियोजना को एयरोस्पेस क्षेत्र की बड़ी कंपनी 'एयरबस' किसी भारतीय निकाय के साथ मिलकर क्रियान्वित करेगी क्योंकि इसे रक्षा क्षेत्र में मेक इन इंडिया पहल के व्यापक ढांचे के तहत लागू किया जाएगा। निर्णयों के अनुसार 16 सी-295 परिवहन विमानों की क्रियाशील दशा में एयरबस द्वारा आपूर्ति की जाएगी जबकि 40 विमानों का भारत में निर्माण किया जाएगा। सूत्र ने बताया कि विमानों के लिए खरीद प्रक्रिया करीब करीब पूरी हो गयी है और शीघ्र ही सौदे पर अंतिम निर्णय लिये जाने संभावना है। एक रिपोर्ट में रक्षा मंत्रालय ने कहा कि भारतीय उत्पादन एजेंसी की भागीदारी में एयरबस से 56 सी-295 की खरीद का मामला मंजूरी के स्तर पर है तथा सौदे पर निकट भविष्य में हस्ताक्षर हो जाने की संभावना है।

क्या होती है ब्लू इकोनॉमी, इससे क्या होगा भारत के आम लोगों पर असर

नई दिल्ली। आईपीटी नेटवर्क

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केरल और कर्नाटक राज्य की चर्चा करते हुए बताया कि अन्य दक्षिण भारतीय राज्यों जैसे तटीय राज्यों में नीली अर्थव्यवस्था (ब्लू इकोनॉमी) विकसित करने के लिए व्यापक योजना चलाई जा रही है। उन्होंने कहा कि नीली अर्थव्यवस्था आत्मनिर्भर भारत का महत्वपूर्ण स्रोत होगी। बंदरगाहों तथा तटीय सड़कों को कनेक्ट किया जा रहा है और इसका फोकस मल्टीमोड कनेक्टिविटी पर है। उन्होंने कहा कि हम अपने तटीय क्षेत्र को जीवन यापन की सुगमता तथा व्यापार-सुगमता के रोल मॉडल में बदलने के उद्देश्य से काम कर रहे हैं।

क्या होती है ब्लू इकोनॉमी

भारत के कुल व्यापार का 90 फीसदी हिस्सा समुद्री मार्ग के जरिए होता है। समुद्री रास्तों, नए बंदरगाहों और समुद्री सामरिक नीति के जरिये अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना ही ब्लू इकोनॉमी कहलाता है। केंद्र सरकार ब्लू इकोनॉमी को बढ़ावा देना चाहती है। आपको बता दें कि भारत तीन ओर से समुद्र से घिरा हुआ है। ऐसे में ब्लू इकोनॉमी पर फोकस बढ़ाकर देश की आर्थिक ग्रोथ को बढ़ाया जा सकता है।

कैसे काम करती है ब्लू इकोनॉमी?

इसमें सबसे पहले समुद्र आधारित बिजनेस

मॉडल तैयार किया जाता है, साथ ही संसाधनों को ठीक से इस्तेमाल करने और समुद्री कचरे से निपटने के डायनामिक मॉडल पर कम किया जाता है। पर्यावरण फिलहाल दुनिया में एक बड़ा मुद्दा है ऐसे में ब्लू इकोनॉमी को अपनाना इस नज़रिये से भी बेहद फायदेमंद साबित हो सकता है। ब्लू इकोनॉमी के तहत फोकस खनिज पदार्थों समेत समुद्री उत्पादों पर होता है। समुद्र के जरिये व्यापार का सामान भेजना ट्रकों, ट्रेन या अन्य साधनों के मुकाबले पर्यावरण की दृष्टि से बेहद साफ़-सुथरा साबित होता है।

क्या होगा आम आदमी पर असर

प्रधानमंत्री ने बताया कि मछुआरा समुदाय की चर्चा सिर्फ समुद्री धन पर निर्भर हैं बल्कि इसके रक्षक भी सरकार ने तटीय इकोसिस्टम के संरक्षण और समृद्धि के लिए अनेक कदम उठाए हैं। इन कदमों में गहरे समुद्र में काम करने वाले मछुआरों की सहायता, अलग मछली पालन विभाग, सस्ता लोन, मछली पालन के काम में लगे लोगों को किसान क्रेडिट कार्ड देना शामिल है. इससे कारोबारियों और सामान्य मछुआरों को मदद मिल रही है।

प्रधानमंत्री ने हाल में लॉन्च की गई 20 हजार करोड़ रुपये की मत्स्य संपदा योजना की भी चर्चा की। इस योजना से केरल तथा कर्नाटक में लाखों मछुआरे प्रत्यक्ष रूप से लाभान्वित होंगे। भारत मछली उत्पाद निर्यात में तेजी से प्रगति कर रहा है। भारत को गुणवत्ता सम्पन्न सी फूड प्रोसेसिंग हब में बदलने के सभी कदम उठाए जा रहे हैं। भारत समुद्री शैवाल की बढ़ती मांग पूरी करने में प्रमुख भूमिका निभा सकता है, क्योंकि किसानों को समुद्री शैवाल लगाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है।

सैमसंग करेगा 5 अरब डॉलर का कारोबार

ओएलईडी डिस्प्ले पैनल बनेगा कमाई का जरिया

नई दिल्ली। एजेंसी

सैमसंग डिस्प्ले की ओर से निर्मित किए जाने वाले ओएलईडी पैनल द्वारा साल 2021 की पहली तिमाही में 5 अरब डॉलर के कारोबार की संभावना जताई जा रही है। मार्केट रिसर्च फर्म ओमडिया की एक नई रिपोर्ट के मुताबिक, ओएलईडी पैनलों के लिए सैमसंग की बिक्री में साल 2021 की पहली तिमाही में 5.18 अरब डॉलर से अधिक का इजाफा हो सकता है और इसका पूरा श्रेय ओएलईडी स्क्रीन्स को अपनाए जाने में हो रही वृद्धि को जाता है।

पिछले साल कंपनी ने पहली तिमाही में ओएलईडी पैनलों से 3.9 अरब डॉलर का मुनाफा कमाया था, जबकि इस साल इसमें 30 फीसदी का इजाफा देखने को मिल रहा है और ऐसा 5जी स्मार्टफोन्स में ओएलईडी पैनलों के इस्तेमाल में हो रही वृद्धि के चलते देखने को मिल रहा है। ओएलईडी डिस्प्ले में ईमेज क्वॉलिटी सामान्य से काफी बेहतर होती है – बेहतर कंट्रास्ट, हाई ब्राइटनेस, बेहतर व्यू एंगल, कलर रेंज में विविधता और अधिक तेज रिफ्रेश रेट्स इसके मुख्य फीचर्स हैं। इसके साथ ही दुनिया की दिग्गज आईटी कंपनियों में शुमार सैमसंग, अब उत्तर प्रदेश में मोबाइल और आईटी डिसप्ले उत्पादों का निर्माण करेगी. सैमसंग की यह यूनिट इससे पहले चीन में स्थापित थी. नोएडा में स्थापित होने जा रहे सैमसंग के इस नए मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की स्थापना से प्रदेश में करीब 4825 करोड़ रुपये का निवेश होगा। यही नहीं भारत, ओएलईडी तकनीक से निर्मित मोबाइल डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग करने वाला दुनिया का तीसरा देश भी बन जाएगा। विश्व में टीवी, मोबाइल फोन, टैबलेट, घड़ियों आदि में उपयोग होने वाले कुल डिस्प्ले उत्पाद का 70 प्रतिशत से अधिक सैमसंग द्वारा दक्षिण कोरिया, वियतनाम तथा चीन में निर्मित होता है। डिस्प्ले इकाईयों का प्रस्तावित निवेश मूल उत्पाद का एक ज्यादा लागत वाला हाई टेक्नोलॉजी कंपोनेन्ट है, जो बीच की सप्लाई चेन की कड़ी को पूर्ण करने के लिये तथा भविष्य में प्रदेश में डिस्प्ले से सम्बन्धित फैब इकाई की स्थापना हेतु यह इकाई एक मील का पत्थर साबित होगी। सैमसंग ग्रुप ने अगले पांच वर्षों में कुल 50 बिलियन डालर का निर्यात लक्ष्य रखा है।

कोरोना वैक्सीन पर बोले AIIMS डायरेक्टर

सही प्रभाव के लिए तय वक्त पर दो डोज जरूरी

नई दिल्ली। एजेंसी

नए साल पर देश के लोगों को सरकार की ओर से एक खास तोहफा मिला, जहां कोरोना वायरस की दो वैक्सीन को मंजूरी दे दी गई। इसके बाद से अफवाहों का दौर जारी है। जिस पर अब दिल्ली एम्स के डायरेक्टर डॉ. रणदीप गुलेरिया (Dr Randeep Guleria) ने सफाई दी है। साथ ही वैक्सीन को पूरी तरह सुरक्षित बताया। बस वैज्ञानिकों की ओर से तय की गई डोज ही तय समय पर इंसान को मिलनी चाहिए। उन्होंने भारत बायोटेक की कोवैक्सीन को आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक बड़ा कदम बताया है।

डॉ. गुलेरिया के मुताबिक कोरोना का टीकाकरण स्वेच्छिक है यानी जो लोग लेना चाहते हैं, वहीं लें। इसके अलावा वैक्सीन की दो डोज किसी भी इंसान को दी जानी जरूरी है, जब दूसरी डोज मिल जाएगी उसके 14 दिन बाद शरीर कोरोना के खिलाफ एंटीबॉडी बनाना शुरू करेगा। उन्होंने साफ किया कि भारत में बनी कोवैक्सीन भी कोरोना के खिलाफ उतनी ही कारगर है, जितनी दूसरे देशों में बनी वैक्सीन है। कोरोना वैक्सीन के साइड-इफेक्ट पर डॉ. गुलेरिया ने कहा कि जब भी किसी बीमारी से संबंधित वैक्सीन आती है, तो उसके कुछ दुष्प्रभाव भी रहते हैं। कोरोना वैक्सीन के मामले में भी साइड-इफेक्ट भी हैं, लेकिन वो इतने गंभीर नहीं हैं। कुछ लोगों को वैक्सीन लेने के बाद इंजेक्शन की जगह पर दर्द, शरीर में दर्द, हल्के बुखार जैसी समस्या हो सकती है। ऐसे में घबराने की जरूरत नहीं है, ये एक सामान्य बात है। उन्होंने आगे कहा कि सरकार ने प्राथमिकता वाले समूहों (Priority Groups) का चयन किया है, जिनका टीकाकरण किया जाएगा। पहले समूह में स्वास्थ्यकर्मी और फ्रंटलाइन वर्कर्स शामिल हैं, जबकि दूसरे समूह में 50 वर्ष से अधिक उम्र के लोग और 50 से कम उम्र के विशेष बीमारियों से ग्रसित मरीज शामिल हैं, जिन्हें कोरोना से खतरा ज्यादा है।

कोविड वैक्सीन की मंजूरी से स्वास्थ्य, आर्थिक मोर्चे पर उम्मीदें बढ़ीं: वित्त मंत्रालय रिपोर्ट

नयी दिल्ली। एजेंसी

वित्त मंत्रालय ने अपनी मासिक आर्थिक रिपोर्ट में कहा है कि कोविड-19 वैक्सीन की मंजूरी से स्वास्थ्य और आर्थिक मोर्चे पर आशावाद को बल मिला है। रिपोर्ट के मुताबिक, ''त्योहारी मौसम और सर्दियों के मौसम की शुरुआत के बावजूद कोविड-19 के प्रभावी प्रबंधन, उच्च आवृत्ति संकेतकों में लगातार सुधार और वी-आकार के उभार के साथ ही लॉकडाउन के प्रतिबंधों में ढील दिए जाने से भारतीय अर्थव्यवस्था कोरोना वायरस महामारी का मुकाबला कर सकी।'' रिपोर्ट में आगे कहा गया कि नए साल की शुरुआत लंबे समय से प्रतीक्षित कोविड-19 वैक्सीन की मंजूरी और विभिन्न देशों में टीकाकरण की शुरुआत के साथ हुई। वित्त मंत्रालय की दिसंबर की मासिक आर्थिक समीक्षा में कहा गया, ''दुनिया भर में मामलों में बढ़ोतरी और नए स्ट्रेन की आशंका के बावजूद इससे स्वास्थ्य और आर्थिक मोर्चे, दोनों पर आशावाद को बल मिला।'' रिपोर्ट में कहा गया कि भारत में साप्ताहिक और दैनिक संक्रमण के मामलों में कमी आई है और वह कोविड की गति को झुकाने में सफल रहा है, यानी बीमारी का असर घटने की शुरुआत हो चुकी है। रिपोर्ट में हालांकि ब्रिटेन में सामने आए कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन को लेकर चिंता भी जताई गई। शारीरिक दूरी दिशानिर्देशों को लेकर कमजोरी को लेकर भी रिपोर्ट में चिंता जताई गई है। इसमें कहा गया है कि कोविड- 19 को उचित व्यवहार, सतर्कता और निगरानी को बनाये रखने की जरूरत है।

डिश टीवी इंडिया ने माइ डिशटीवी एप पर 'स्कैन टू हेल्प' फीचर प्रस्तुत किया

डिश-अ-थॉन 2020 की रनर-अप टीम के दिमाग की उपज

इंदौर। आईपीटी नेटवर्क

टेलीविजन देखने का बाधारहित और सुविधाजनक अनुभव प्रदान करने के अपने उद्देश्य पर खरा उतरते हुए भारत की अग्रणी डीटीएच कंपनी, डिश टीवी इंडिया लिमिटेड ने अपने डिश टीवी सब्सक्राइबर्स के लिये एक नया 'स्कैन टू हेल्प' फीचर लॉन्च किया है। डिश-अ-थान 2020 की फर्स्ट रनर-अप टीम (जो आतंरिक टीम, यानी टीम डिशटीवी है) द्वारा निष्पादित और परिकल्पित 'स्कैन टू हेल्प' फीचर माइ डिशटीवी ऐप पर उपलब्ध है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग से चलती है और आसान समझ के लिये हिन्दी और अंग्रेजी भाषा को सपोर्ट करती है। इस फीचर के साथ, कंपनी का लक्ष्य सेट-टॉप बॉक्स पर किसी तकनीकी त्रुटि के मामले में सभी मौजूदा और नये सब्सक्राइबर्स को स्वयं-सहायता के लिये समर्थ बनाना है। इसके अलावा, यह नया फीचर उच्च सी-सैट पाने, डिश टीवी के कॉल सेंटर में कॉल्स की संख्या कम करने और क्रॉस-सेल के अवसर में भी मदद करता है। सब्सक्राइबर्स एरर प्लेट को स्कैन करके स्वयं-सहायता की यात्रा बाधारहित तरीके से शुरू कर सकते हैं और वह आटोमेटिक तरीके से अकाउंट स्टेटस और करंट सब्सक्रिप्शन पर अपडेट साझा करेगा। ब्राडकास्टिंग सेंटर पर मौसम की खराब स्थिति के मामले में, वह सब्सक्राइबर की लोकेलिटी में मौसम की स्थिति का अपडेट लेगा और तकनीकी समस्या दूर करेगा। यह ऐप इस यात्रा में 'सर्विस टिकट' प्राप्त करने का विकल्प भी प्रदान करेगा।नये फीचर के लॉन्च पर टिप्पणी करते हुए डिश टीवी इंडिया लिमिटेड के कार्यकारी निदेशक और ग्रुप सीईओ, श्री अनिल दुआ ने कहा कि, "डिश टीवी इंडिया अपने ग्राहकों को बेजोड़ सेवा और टीवी देखने का अनुभव प्रदान करने के लिये अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी में लगातार निवेश कर रहा है। इस डिजिटल युग में, ग्राहक-संतुष्टि अर्जित करने के लिये टेक्नोलॉजी-संचालित समाधान और पेशकशें सबसे महत्वपूर्ण हैं और यह नया एआई-इनैबल्ड टेक फीचर उसी दिशा में एक कदम है। यह तथ्य इस फीचर को बहुत खास बनाता है कि इसका आइडिया डिश-अ-थान 2020 की शीर्ष 3 विजेता टीमों में से एक ने दिया था। यह एक इन-हाउस टीम, टीम डिशटीवी थी और उन्होंने इस आइडिया से समाधान बनाने और निष्पादन पूर्ण करने के लिये इसे आगे बढ़ाया। 'स्कैन टू हेल्प' जैसे नये फीचर्स एम एंड ई/ब्राडकास्टिंग उद्योग के भविष्य को पुनः परिभाषित करने और आकार देने के लिये तैयार हैं।"

एजीईएल ने 600 मेगावाट विंड-सोलर हाइब्रिड पावर प्रोजेक्ट के लिए एलओए हासिल किया

अहमदाबाद। एजेंसी

अदाणी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ('एजीईएल') की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी, अदाणी रिन्यूएबल एनर्जी होल्डिंग ऐट लिमिटेड ('AREHEightL') ने 31 दिसम्बर 2020 को 600 मेगावाट विंड-सोलर हाइब्रिड पावर प्रोजेक्टस्थापित करने के लिए लेटर ऑफ अवार्ड (एलओए) हासिल किया। AREHEightLने 1,200 मेगावाट आईएसटीएस-कनेक्टेड विंड-सोलर हाइब्रिड पावर प्रोजेक्ट की स्थापना के लिए सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ('एसईसीआई') द्वारा जारी एक निविदा में भाग लिया था। इस प्रोजेक्ट की क्षमता के लिए निर्धारित टैरिफ 25वर्ष की अवधि के लिए 2.41रुपये/किलोवाट आवर है। प्रोजेक्ट पीपीए की प्रभावी तिथि से 18 महीने के अंदर शुरू होने की उम्मीद है। इस प्रोजेक्ट के साथ, एजीईएल की कुल रिन्यूएबल ऊर्जा प्रोजेक्ट क्षमता अब 14,795 मेगावाट हो गई है, जिसमें 2,950 मेगावाट के प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं और 11,845 मेगावाट के प्रोजेक्ट्स अभी कार्यान्वित होने वाले हैं। यह विंड-सोलर हाइब्रिड प्रोजेक्ट, भारत में आरई हाइब्रिड प्रोजेक्ट्स के मामले में एजीईएल की अग्रणी स्थिति को मजबूत करते हैं। हाइब्रिड प्रोजेक्ट्स, ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर के उपयुक्त इस्तेमाल को सक्षम बनाते हैं, जिससे रिन्यूएबल एनर्जी का अधिक टिकाऊ एकीकरण होता है और ये भारत में रिन्यूएबलएनर्जी के विकास को संभव बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस विकास के बारे में बताते हुए, अदाणी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के एमडी और सीईओ, श्री विनीत एस. जैन ने कहाकि 'अदाणी ग्रीन पर्यावरण-अनुकूल भविष्य की ओर जाने के लिए एक स्थायी वातावरण निर्माण करने के लिए प्रतिबद्ध है। 600 मेगावाट विंड-सोलर हाइब्रिड पावर प्रोजेक्ट का एलओए हासिल करना, 2025 तक 25 गीगावॉट की रिन्यूएबल एनर्जी क्षमता प्राप्त करने और 2030 तक दुनिया की सबसे बड़ी रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी बनने की हमारी महत्वाकांक्षा के अनुरूप है और भारत के डिकॉर्बोनाइलेशन के लक्ष्यों में महत्वपूर्ण योगदान देता है। यह भारत में विंड, सोलर और हाइब्रिड पॉवर जेनेरेशन में एजीईएल के नेतृत्वकारी स्थिति को भी मजबूती प्रदान करता है।'

इस साल कैसा रहेगा इंडियन इकॉनमी का हाल, World Bank ने बताया

वॉशिंगटन। एजेंसी

विश्व बैंक (World Bank) ने मंगलवार को कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था (Indian Economy) में वित्त वर्ष 2020-21 में 9.6 प्रतिशत की गिरावट आने का अनुमान है। यह परिवार के स्तर पर व्यय और निजी निवेश में आई कमी को प्रतिबिंबित करता है। वहीं अगले वित्त वर्ष 2021-22 में भारतीय अर्थव्यवस्था में 5.4 प्रतिशत वृद्धि का अनुमान है। विश्व बैंक ने वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट में कहा है कि कोविड-19 महामारी (Covid-19 pandemic) से असंगठित क्षेत्र में काम करने वालों की आय बुरी तरीके से प्रभावित हुई है। इस क्षेत्र में 80 प्रतिशत लोगों को रोजगार मिला हुआ है। इसमें कहा गया है, 'भारत में महामारी ने उस समय अर्थव्यवस्था को प्रभावित किया जब इसमें पहले से गिरावट आ रही थी। वित्त वर्ष 2020-21 में उत्पादन में 9.6 प्रतिशत की गिरावट आने का अनुमान है। यह परिवार की आय और निजी निवेश में तीव्र कमी को बताता है।'

2021-22 में 5.4 प्रतिशत फीसदी वृद्धि

विश्व बैंक ने कहा, 'भारत में आर्थिक वृद्धि दर 2021-22 में सुधरेगी और इसके 5.4 प्रतिशत रहने का अनुमान है। वित्तीय क्षेत्र में कमजोरियों को देखते हुए कमजोर तुलनात्मक आधार पर मिलने वाली तेजी को निजी क्षेत्र की तरफ से कम निवेश प्रभावित करेगा।' रिपोर्ट के अनुसार असंगठित क्षेत्र की कुल रोजगार में हिस्सेदारी 80 प्रतिशत है। इसमें महामारी के दौरान आय का काफी नुकसान हुआ। हाल में बिजली खपत, पीएमआई (परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स) जीएसटी संग्रह जैसे आंकड़े को देखने से यह संकेत मिलता है कि सेवा और विनिर्माण क्षेत्र में रिवाइवल तेजी से हो रहा है।

पड़ोसी पाकिस्तान का हाल

विश्व बैंक ने पाकिस्तान के बारे में कहा कि वहां रिवाइवल हल्का रहेगा और वृद्धि दर 2020-21 में 0.5 प्रतिशत रहने का अनुमान है। लगातार राजकोषीय मजबूती को लेकर दबाव और सेवा क्षेत्र में कमजोरियों को देखते हुए वृद्धि पर असर पड़ने की आशंका है। दक्षिण एशिया के अन्य देशों में कोविड-19 का प्रभाव अपेक्षाकृत कुछ कम रहा है लेकिन उसके बाद भी वे काफी प्रभावित हुए हैं। जो अर्थव्यवस्थाएं पर्यटन और यात्रा पर काफी हद तक निर्भर थे, उनपर काफी प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। इसमें मालदीव, नेपाल और श्रीलंका शामिल हैं।

रिपोर्ट के अनुसार दक्षिण एशिया में वृद्धि दर 3.3 प्रतिशत रहने का अनुमान है। विश्व बैंक ने 2021 में वैश्विक अर्थव्यवस्था में चार प्रतिशत वृद्धि का अनुमान जताया है। दुनिया के कई देशों में कोविड- 19 टीके को मिली मंजूरी के बीच जताया गया यह अनुमान महामारी से पहले के 5 प्रतिशत वृद्धि की प्रवृति के मुकाबले कम है। वहीं रिपोर्ट में 2022 में वैश्विक अर्थव्यवस्था में 3.8 प्रतिशत वृद्धि का अनुमान लगाया गया है। इसके मुताबिक 2020 में विश्व अर्थव्यवस्था में 4.3 प्रतिशत की गिरावट का अनुमान लगाया गया है।

News यू केन USE

स्पेक्ट्रम नीलामी के लिये एक मार्च से होंगी बोलियां शुरू: दूरसंचार विभाग

नयी दिल्ली। एजेंसी

छठे दौर में 3.92 लाख करोड़ रुपये की स्पेक्ट्रम नीलामी के लिये बोलियों की प्रक्रिया एक मार्च से शुरू होंगी। बुधवार को जारी एक सरकारी नोटिस में इसकी जानकारी दी गयी है। केंद्रीय मंत्रिमंडल से 2,251.25 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम की नीलामी की मंजूरी पहले ही मिल चुकी है। इनकी कीमत 17 दिसंबर 2020 की आधार दर के हिसाब से 3.92 लाख करोड़ रुपये है। दूरसंचार विभाग (डीओटी) ने प्री-बिड कांफ्रेंस के लिये 12 जनवरी का समय तय किया है। इस नोटिस को लेकर 28 जनवरी तक स्पष्टीकरण मांगा जा सकता है। नीलामी में भाग लेने के लिये दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को पांच फरवरी तक आवेदन दायर करना होगा। नोटिस के अनुसार, बोलीदाताओं की अंतिम सूची की घोषणा 24 फरवरी को होगी। इस दौर में 700 मेगाहर्ट्ज, 800 मेगाहर्ट्ज, 900 मेगाहर्ट्ज, 2100 मेगाहर्ट्ज, 2300 मेगाहर्ट्ज और 2500 मेगाहर्ट्ज के लिये बोलियां एक मार्च से शुरू होने वाली हैं।

पश्चिम बंगाल सरकार ने ओएनजीसी के लिए जमीन को मंजूरी दी

कोलकाता। एजेंसी

पश्चिम बंगाल मंत्रिमंडल ने मंगलवार को ओएनजीसी को तेल खोज के लिए उत्तर परगना जिले के अशोकनगर में 13.49 एकड़ जमीन देने की मंजूरी दे दी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने महारत्न कंपनी के तेल उत्खनन से राज्य को होने वाले फायदों की चर्चा करते हुए कहा कि इससे राज्य में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और अर्थव्यवस्था में सुधार होगा। बनर्जी ने कहा कि जमीन एक रुपये में दी जाएगी। उन्होंने कहा, "ओएनजीसी हमें सलामी के रूप में 6.5 करोड़ रुपये देना चाहती थी, लेकिन मंत्रिमंडल ने आर्थिक लाभ को देखते हुए जमीन एक रुपये में देने का फैसला किया।" सलामी किराएदार द्वारा संपत्ति मालिक को दिया जाने वाला भुगतान है। बनर्जी ने संवाददाताओं से कहा, "राज्य सरकार मुफ्त में जमीन नहीं दे सकती। मैं राज्य सरकार को एक रुपये दूंगी, क्योंकि मैं राज्य के लिए योगदान करना चाहती हूं और यह परियोजना तुरंत शुरू होनी चाहिए।"

उद्योगों में गुणवत्ता, उत्पादकता को बढ़ावा देने के लिए उद्योग मंथन का आयोजन

नयी दिल्ली। सरकार ने मंगलवार को कहा कि भारतीय उद्योग में गुणवत्ता और उत्पादकता को बढ़ावा देने के लिए क्षेत्रवार 'उद्योग मंथन' के नाम से वेब गोष्ठी की एक श्रृंखला का आयोजन चार जनवरी से दो मार्च के बीच किया जा रहा है। एक आधिकारिक बयान के मुताबिक उद्योग मंथन चुनौतियों, अवसरों की पहचान करेगा और समाधान तथा सबसे बढ़िया तौर-तरीकों पर विचार करेगा। वाणिज्य मंत्रालय ने कहा, "यह बातचीत उद्योगों और क्षेत्रों में गुणवत्ता तथा उत्पादकता बढ़ाने के लिए 'वोकल फॉर लोकल' को बढ़ावा देने और आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने में योगदान करेगी।" इस वेब गोष्ठी का आयोजन वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत आने वाले उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी), भारतीय गुणवत्ता परिषद, राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद और उद्योग संघ मिलकर कर रहे हैं।

केदारनाथ धाम

सृष्टि का सूत्रपात स्थल

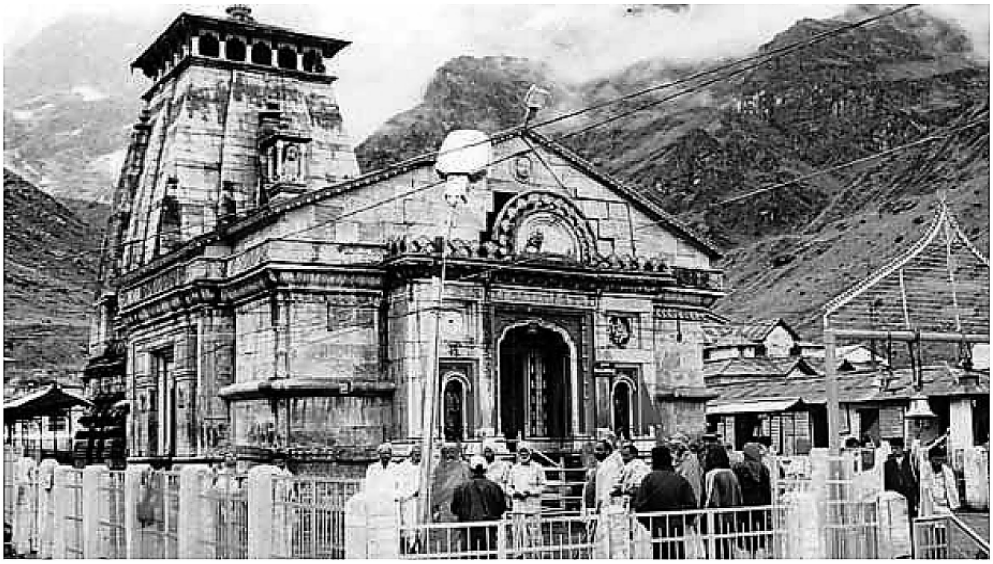

भगवान भोले शंकर कहते हैं कि हिमालय की केदार घाटी में मैं सदैव वास करता हूं। सृष्टि की रचना इसी केदार क्षेत्र में ही ब्रह्मा रूप धारण करके प्रारंभ की और धरती पर यह केदारखंड भू स्वर्ग है। केदारनाथ का प्राचीन मंदिर सागर तल से लगभग 3600 मीटर की ऊंचाई पर कलकल करती पवित्र मंदाकिनी के तट पर है, जिसका जीर्णोद्धार आदि शंकराचार्य ने किया था।

केदारनाथ में कोई निर्मित मूर्ति नहीं है। एक बहुत बड़ा त्रिकोण पर्वत खंड है। यात्री स्वयं जाकर पूजा करते हैं और अंगमाल देते हैं। मंदिर है तो प्राचीन पर साधारण है। श्री केदार मंदिर में ऊषा, अनिरुद्ध, पांच पांडव, श्रीकृष्ण तथा शिव-पार्वती की मूर्तियां हैं। मंदिर के बाहर परिक्रमा के पास अमृत कुंड, इशान कुंड, हंस कुंड, रेतस कुंड आदि तीर्थ हैं। वहां के दर्शनीय स्थान भृगु पंथ (मन्न गंगा), क्षीर गंगा, वासुकि ताल, गुगू कुंड एवं भैरव शिला हैं। आदि शंकराचार्य ने मंदिर के निकट ही देह त्याग की तथा उनकी समाधि स्थापित है।

द्वादश ज्योतिर्लिंगों में केदारेश्वर पांचवां-

सतयुग में उपमन्यु जी ने यहीं भगवान शंकर की आराधना की थी। द्वापर में पांडवों ने यहां तपस्या की। यह केदार क्षेत्र अनादि है। महिष रूपधारी भगवान शंकर के विभिन्न अंग पांच स्थानों पर प्रतिष्ठित हैं, जिन्हें पञ्च केदार माना जाता है। प्रथम केदारनाथ में पृष्ठ भाग, द्वितीय मदमहेश्वर में नाभि, तृतीय केदार तुंगनाथ में बाहु, चतुर्थ केदार रुद्रनाथ में मुख तथा पञ्चम केदार कल्पेश्वर में जटा और पशुपतिनाथ नेपाल में सिर माना जाता है।

द्वारका ज्योतिर्लिंग का विवरण

सौराष्ट्रं सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम्।
उज्जयिन्यां महाकालमोकारे परमेश्वरम्॥
केदारं हिमवत्पृष्ठे डाकिन्यां भीमशंकरम्॥
वाराणास्यां च विश्वेशं त्र्यम्बकं गौमती तटे॥
वैद्यनाथं चिताभूमौ नागेशं दारुकावने।।
सेतुबंधेच रामेशं घुश्मेशं तु शिवालये॥
द्वादशै तानि नामानि प्रातरुत्थाय यः पठेत।
सर्वपापै विनिर्मुक्त : सर्वसिद्धिफलं लभेत॥

अर्थ : 1. गुजरात काठियावाड़ में सोमनाथ, 2. तमिलनाडु में मल्लिकार्जुन, 3. मध्य प्रदेश उज्जैन में महाकाल, 4. ओंकारेश्वर नर्मदा तट पर, 5. उत्तराखंड में केदारनाथ, 6. श्री भीमशंकर (महाराष्ट्र), 7. काशी (उत्तर प्रदेश), 8. त्र्यम्बकेश्वर गोदावरी के तट पर, 9. वैद्यनाथ धाम (चिता भूमि), 10. नागेश (गुजरात), 11. श्री रामेश्वरम सागर तट (तमिलनाडु) तथा 12. श्री घुश्मेश्वर। व्यक्ति प्रात:काल उठकर प्रतिदिन पाठ करने पर पापों से मुक्ति तथा सभी सिद्धियों का पल पाता है।

इस वर्ष के प्रथम दर्शन-

भारी हिमपात के कारण केदारनाथ मंदिर एवं गौरीकुंड मार्ग अवरुद्ध हो गया था, जिसे उत्तराखंड सरकार ने समय रहते गोरखा कुलियों को विशेष रूप से लगाकर चलने लायक रास्ता बना दिया। 28 अप्रैल को देश-विदेश से केवल 1099 श्रद्धालु ही किवाड़ खुलने पर उपस्थित थे। प्रात: 7:30 बजे वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ मंदिर के रावल एवं मुख्य पुजारी की उपस्थिति में पारंपरकि वाद्य यंत्रों एवं सिख रेजीमेंट के बैंड की मधुर ध्वनि के बीच बाबा केदारनाथ के कपाट खोले गए। श्रद्धालुओं ने शांति के साथ पंक्तिबद्ध होकर बाबा केदार के जयकारों के साथ दर्शन किए।

हमारी आस्था

कड़ाके की सर्दी में श्रद्धा, भक्ति का अद्भुत दृश्य देखने को मिला। सबसे पहले रावल भीमा शंकरलिंग तथा मुख्य पुजारी श्री शंकरलिंग ने मंदिर में प्रवेश किया। इस अवसर पर रिलायंस समूह के चेयरमैन उद्योगपति अनिल अंबानी, केदारनाथ विधायिका शैला रानी रावत, धर्म प्रचार मंडल के प्रधान राम महाजन, डी.एम. डा. नीरज खैरवाल एवं मंदिर समिति के अधिकारीगण मौजूद थे। सुबह से लेकर शाम तक पांच हजार श्रद्धालुओं ने दर्शन किए, जिनमें मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री साध्वी उमा भारती भी थीं।

साधू का लंगर-

बर्फ के कारण बाजार बंद था, मगर एक साधू ने श्रद्धालुओं के लिए लंगर की व्यवस्था की हुई थी। भारी ठंड के कारण एक पुजारी के पुत्र सहित छह-सात यात्री स्वर्ग सिधार गए।

विष्णु तीर्थ की नारायण कुटी

विश्व प्रसिद्ध साधना केंद्र

देवास के ऐसे विश्व प्रसिद्ध साधना केंद्र पर जहां कभी राजा विक्रमादित्य के भाई ऋषि भर्तहरी ने साधना की थी, उक्त साधना स्थान आज नारायण कुटी के नाम से प्रसिद्ध है। इस साधना कुटी को ब्रह्मलीन गुरुदेव स्वामी विष्णु तीर्थ महाराज ने सन् 1951 में अपनी तपोभूमि बनाया। इसके पूर्व यहां स्वामी नारायण सरस्वती नामक एक महात्मा का निवास था, जिस कारण उक्त स्थान का नाम नारायण कुटी हो गया। 1950 में नारायण सरस्वती के ब्रह्मलीन हो जाने पर कुछ समय तक यह कुटी रिक्त पड़ी रही। इसके बाद भक्तों के अनुरोध पर स्वामी विष्णु तीर्थ ने इसे अपना निवास बना लिया। इससे पूर्व स्वामी जी ने 1940 में स्वामी शंकर पुरुषोत्तमतीर्थ से हरिद्वार में दीक्षा ग्रहण कर समूचे भारत का भ्रमण किया।

कुटी के समीप ही गुरु महाराज ने साधना के लिए गुफा का निर्माण भी कराया। ऐसी मान्यता है कि उक्त गुफा में आज भी कोई दो साधु साधनारत हैं। कुटी के समीप ही भगवान शंकर का मंदिर है। स्वामी जी के सानिध्य के चलते धीरे-धीरे यह साधना स्थल संन्यास, दीक्षा और शक्तिपात का आश्रम बनता गया। बाद में उक्त कुटिया के आस-पास संन्यासियों और अतिथियों के लिए निर्माण कार्य किया गया।

गुरु परंपरा

सर्वप्रथम श्रीगंगाधर तीर्थ ने शक्तिपात परंपरा की शुरुआत की थी। इनके बाद क्रमश: स्वामी नारायण तीर्थ देव, स्वामी शंकर तीर्थ पुरुषोत्तम, गोगानंद महाराज, स्वामी विष्णु तीर्थ महाराज और शिवोम तीर्थ महाराज। ये सभी संन्यास, दीक्षा देने वाले गुरु थे। शिवोम तीर्थ महाराज से दीक्षा लेकर वर्तमान में यहां के पीठाधीश हैं स्वामी सुरेशानंद महाराज।

स्वामी विष्णु तीर्थ महाराज के प्रमुख शिष्य थे स्वामी शिवोम तीर्थ महाराज, जिन्होंने उक्त आश्रम की परंपरा का देश भर में प्रचार-प्रसार किया। कुछ माह पूर्व ही शिवोम तीर्थ भी ब्रह्मलीन हो गए। उन्होंने विष्णु तीर्थ महाराज से सन् 1959 को शक्तिपात द्वारा दीक्षा ली थी।आश्रम से जुड़े सैकड़ों साधकों के लिए यह एक ध्यान, भजन, पूजन और गुरु वंदना का केंद्र है। भक्तों की मान्यता है कि विष्णु तीर्थ महाराज आंतरिक शक्तियों से संपन्न एक ऐसे गुरु है, जो साधकों के लिए आज भी उपलब्ध हैं। उनके चमत्कार के अनेक किस्से हैं। वह जो भी व्यक्ति मुमुक्षु होता था उसे शक्तिपात द्वारा दीक्षा देते थे। शक्तिपात के बाद उक्त व्यक्ति के मन में संसार के प्रति वैराग्य भाव उत्पन्न हो जाता है।

सन् 1969 में विष्णु तीर्थ महाराज ऋषिकेश में गंगा के किनारे नश्वर देह का त्याग कर ब्रह्मलीन हो गए। आज देश और देश के बाहर भी इस आश्रम की अनेक शाखाएं है : जैसे- इंदौर, रायपुर, रायसेन, डबरा, मुम्बई, हरियाणा, कर्नाटक और देश के बाहर अमेरिका तथा ब्रिटेन में उक्त कुटी के साधकों की जमात है।

कैसे पहुंचे : इंदौर से 35 किलोमीटर दूर देवास में ट्रेन या बस द्वारा पहुंचा जा सकता है, जहां पर माताजी की टेकरी के नीचे स्थित है नारायण कुटी।

मकर संक्रांति का धार्मिक महत्व

जिस प्रकार तिल और गुड़ के मिलने से मीठे-मीठे लड्डू बनते हैं उसी प्रकार विविध रंगों के साथ जिंदगी में भी खुशियों की मिठास बनी रहे। जीवन में नित नई ऊर्जा का संचार हो और पतंग की तरह ही सभी सफलता के शिखर तक पहुंचे। कुछ ऐसी ही शुभकामनाओं के साथ सूर्य पर्व मकर संक्रांति पूरी श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जाता है।

क्या है मकर संक्रांति : प्रति माह होने वाला सूर्य का निरयण राशि परिवर्तन संक्रांति कहलाता है। सामान्यतया आमजन को सूर्य की मकर संक्रांति का पता है, क्योंकि इस दिन दान-पुण्य किया जाता है। इसी दिन सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण होते हैं। संक्रांति को सजीव माना गया है। प्रति माह संक्रांति अलग-अलग वाहनों व वस्त्र पहनकर, शस्त्र, भोज्य पदार्थ एवं अन्य पदार्थों के साथ आती है। सूर्य का एक राशि से दूसरी राशि में जाने को ही संक्रांति कहते हैं। एक संक्रांति से दूसरी संक्रांति की अवधि ही सौरमास है। वैसे तो सूर्य संक्रांति 12 हैं, लेकिन इनमें से चार संक्रांति महत्वपूर्ण हैं, जिनमें मेष, कर्क, तुला, मकर संक्रांति हैं। मकर संक्रांति के शुभ मुहूर्त में स्नान, दान व पुण्य का शुभ समय का विशेष महत्व है। मकर संक्रांति के पावन पर्व पर गुड़ व तिल लगाकर नर्मदा में स्नान करना लाभदायी होता है। इसके पश्चात दान संक्रांति में गुड़, तेल, कंबल, फल, छाता दान से जातकों को लाभ मिलेगा। जातकों को गुड़ व तिल से स्नान करना व दान-पुण्य करना लाभदायक रहता है।

संक्रांति का धार्मिक महत्व

■पुराणों के अनुसार मकर संक्रांति के दिन सूर्य अपने पुत्र शनि के घर एक महीने के लिए जाते हैं, क्योंकि मकर राशि का स्वामी शनि है। हालांकि ज्योतिषीय दृष्टि से सूर्य और शनि का तालमेल संभव नहीं, लेकिन इस दिन सूर्य खुद अपने पुत्र के घर जाते हैं। इसलिए पुराणों में यह दिन पिता-पुत्र के संबंधों में निकटता की शुरुआत के रूप में देखा जाता है।■इस दिन भगवान विष्णु ने असुरों का अंत करके युद्ध समाप्ति की घोषणा की थी। उन्होंने सभी असुरों के सिरों को मंदार पर्वत में दबा दिया था। इसलिए यह दिन बुराइयों और नकारात्मकता को खत्म करने का दिन भी माना जाता है।■एक अन्य कथा के अनुसार गंगा को धरती पर लाने वाले महाराज भगीरथ ने अपने पूर्वजों के लिए इस दिन तर्पण किया था। उनका तर्पण स्वीकार करने के बाद इस दिन गंगा समुद्र में जाकर मिल गई थी। इसलिए मकर संक्रांति पर गंगा सागर में मेला लगता है।

सतर्क रहते हुये 2021 के लिये वृद्धि योजनाओं पर अमल कर रहा वाहन उद्योग

नयी दिल्ली। एजेंसी

वाहन उद्योग के लिये त्रासद रहा साल 2020 समाप्त हो चुका है। हालांकि, अभी भी बाजार पर आपूर्ति श्रृंखला की बाधाओं समेत कई चुनौतियों का असर जारी रहेगा, लेकिन कई वाहन कंपनियां 2021 में वृद्धि की अपनी योजनाओं में तेजी लाने पर काम कर रही हैं। किआ मोटर्स उत्पादन को तेज करने का प्रयास कर रही है, तो टोयोटा का जोर बाजार में नये उत्पाद पेश करने पर है। हुंदै ऐसे नवोन्मेषों पर ध्यान केंद्रित करने की रणनीति बना रही है, जो बाजार के लिये पहला व नया हो। किआ मोटर्स के प्रबंध निदेशक (एमडी) एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) कोख्युन शिम ने कहा, ''हम नये साल में किआ के कारों की बढ़ती उपभोक्ता मांग को पूरा करने के लिये अपने विनिर्माण संयंत्र में तीन पारियों में काम करेंगे। हम एक सहज, सुरक्षित और अतुलनीय ग्राहक अनुभव प्रदान करने के लिये कोविड-19 के बाद के डिजिटल संसार में अपने नेटवर्क के साथ अपने 'फिजिटल' मॉडल को मजबूत करेंगे।'' कंपनी का आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले में विनिर्माण संयंत्र है, जिसकी क्षमता लगभग तीन लाख इकाई प्रति वर्ष की है। शिम ने कहा कि चुनौतियों के बावजूद कंपनी ने 2020 में दो नये खंडों में सफलतापूर्वक प्रवेश किया और अभी देश में अपने पहले उत्पाद उतारने के सिर्फ 16 महीनों के भीतर चौथे स्थान पर पहुंच गयी है। इसी तरह, टोयोटा किर्लोस्कर मोटर के वरिष्ठ उपाध्यक्ष (बिक्री एवं सेवा) नवीन सोनी ने कहा कि 2021 में बढ़ी हुई मांग और ग्राहकों की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिये कंपनी ने एक स्थायी और चरणबद्ध तरीके से अपने उत्पाद लाइन-अप का विस्तार करने की योजना बनायी है। उन्होंने कहा, ''हम मध्य से दीर्घकालिक रणनीति के रूप में आवागमन के वैकल्पिक समाधानों पर भी ध्यान केंद्रित करना चाहेंगे, जैसे कि इलेक्ट्रिक वाहन।'' हुंदै की योजनाओं पर कंपनी एमडी एवं सीईओ एसएस किम ने कहा, ''भारतीय बाजार के प्रति गहरी प्रतिबद्धता के साथ हम अपनी योजनाओं पर कायम रहेंगे और तकनीकी रूप से श्रेष्ठ व उद्योग के लिये प्रथम नवाचारों के साथ अपने नेतृत्व को मजबूत करेंगे।'' इसी तरह, टाटा मोटर्स के एमडी एवं सीईओ गुंतर बुत्शेक ने कहा, ''हम अपने ग्राहकों को खुश करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। हम सुरक्षा, दक्षता, गुणवत्ता और आराम के लिये प्रासंगिक उत्पादों को पेश करके ग्राहकों की गतिशीलता की नयी जरूरतों को व्यापक रूप से संबोधित करते हैं।'' होंडा कार्स इंडिया के वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवं निदेशक (विपणन व बिक्री) राजेश गोयल ने कहा कि संचालन में सफलतापूर्वक सुधार के बाद कंपनी के उत्पादन की मात्रा में तेजी आयी है। फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन (फाडज्ञ) के अध्यक्ष विंकेश गुलाटी ने कहा कि मौजूदा चुनौतियों के बावजूद वाहन उद्योग अब रोमांचक समय में प्रवेश करने की कगार पर है, क्योंकि भारत एक बार फिर से यात्री वाहन खंड में वैश्विक स्तर पर तीसरा स्थान हासिल करने के लिये अपनी गति बढ़ायेगा।

चीन को बड़ा झटकाः लीथियम के लिए भारत ने किया अर्जेंटीना से एग्रीमेंट, चिली और बोलिविया पर भी नजर

नई दिल्ली। भारत की तरफ से चीन के खिलाफ लगातार आर्थिक रूप से निर्भरता खत्म करने की कोशिशें हो रही हैं। इसी क्रम में भारत ने हाल ही में बनाई सरकारी कंपनी खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड के जरिए अर्जेंटीना की एक फर्म के साथ एक समझौता किया है। ये समझौता लीथियम के लिए किया गया है, जिसका इस्तेमाल रीचार्जेबल बैटरियों में किया जाता है। ये बैटरियां इलेक्ट्रिक व्हीकल, लैपटॉप और मोबाइल फोन आदि को पावर देने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं।

खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड को अगस्त 2019 में बनाया गया था। इसे तीन सरकारी कंपनियों NALCO, हिंदुस्तान कॉपर और मिनरल एक्सप्लोरेशन लिमिटेड ने मिलकर बनाी है, जिसके जरिए लीथियम और कोबाल्ट जैसे असेट्स को विदेशों से खरीदा जा सके। चिली और बोलिविया भी लीथियम का उत्पादन करने वाले टॉप देशों में शामिल हैं, जिन पर भी भारत की नजर है।

मौजूदा समय में भारत इन सेल के लिए आयात पर निर्भर है, लेकिन इसे बनाने वाले रॉ मटीरियल लीथियम में की गई डील चीन को टक्कर देने वाली साबित हो सकती है। हालांकि, लीथियम से डील में भारत देरी से जरूर आया है, क्योंकि अब इलेक्ट्रिक व्हीकल पर जोर दिया जाना शुरू किया जा चुका है।

सबसे अच्छी होती हैं सॉलिड स्टेट बैटरियां, जो aqueous electrolyte solutions के विकल्प का इस्तेमाल कर के बनती हैं। इसमें आग लगने का खतरा कम होता है और तेजी से चार्ज होती है। ये बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल को सिर्फ 10 मिनट में चार्ज कर सकती है, जिसके चलते रीचार्ज करने का समय तो-तिहाई घट जाता है। इन बैटरियों की मदद से एक इलेक्ट्रिक व्हीकल की माइलेज बढ़ जाती है।

लीथियम आयन बैटरियों में पिछले सालों में काफी बेहतरी के काम हुए हैं फिर भी बैटरी को चार्ज होने में देरी होना और एनर्जी डेंसिटी कमजोर होने की दिक्कतें अभी भी आती हैं। लीथियम आयन बैटरियां फोन और लैपटॉप के लिए शानदार साबित हुई हैं। वहीं इलेक्ट्रिक व्हीकल के मामले में अभी भी ये बैटरियां कमजोर साबित हो रही हैं और उन्हें दूर करने के लिए इसे और एडवांस करने की जरूरत है।

हुंदै ने नयी आई-20 प्रीमियम हैचबैक का निर्यात शुरू किया

नयी दिल्ली। एजेंसी

हुंदै मोटर इंडिया लि. (एचएमआईएल) ने अपनी पूरी तरह नयी आई20 प्रीमियम हैचबैक का निर्यात शुरू कर दिया है। कंपनी 'आत्मनिर्भर भारत' के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को मजबूत कर रही है। कंपनी ने सोमवार को बयान में कहा कि नयी आई20 की पहली 180 कारों की खेप को दक्षिण अफ्रीका, चिली और पेरू भेजा जा रहा है। कंपनी ने पिछले साल नवंबर में भारत में चौथी पीढ़ी के आई20 मॉडल की घोषणा की थी। इसकी शोरूम कीमत 6.79 लाख से 11.17 लाख रुपये है। आई20 को 2007 में पेश किया गया था। यह मॉडल वैश्विक बाजार में काफी लोकप्रिय है। कंपनी ने नवंबर, 2020 तक इसकी 5.16 लाख इकाइयों का निर्यात किया था। एचएमआईएल के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) एस एस किम ने कहा, ''नयी आई20 के वैश्विक बाजारों को निर्यात के साथ हमने 'मेक इन इंडिया' के प्रति प्रतिबद्धता पूरी की है। पहले ही हम आई20 की 5.16 लाख इकाइयों का निर्यात कर चुके हैं। यह वैश्विक बाजारों में लोकप्रिय ब्रांड है।''

बोतलबंद पेयजल में कैल्शियम, मैग्नीशियम की सीमा अनुपालन के लिये एफएसएसएआई ने दिया और समय

नयी दिल्ली। एजेंसी

खाद्य नियामक एफएसएसएआई ने मिनरल वाटर को छोड़ अन्य बोतलबंद पेयजल में कैल्शियम और मैग्नीशियम की सीमा से संबंधित नियमों का पालन करने के लिये खाद्य व्यापार ऑपरेटरों (एफबीओ) को दिया गया समय एक जुलाई 2021 तक के लिये बढ़ा दिया है। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) ने इससे पहले भी समय सीमा को एक जुलाई 2020 और बाद में एक जनवरी 2021 तक बढ़ा दिया था। एफएसएसएआई ने एक बयान में कहा कि हितधारकों के एक वर्ग से ज्ञापन प्राप्त हुआ है। इसमें कहा गया है कोविड-19 महामारी के कारण नियमों का पालन करने के लिये एफबीओ अभी तक तैयार नहीं हैं। नियामक ने कहा, ''पैकेज्ड ड्रिंकिंग वॉटर (मिनरल वाटर के अलावा) के मानकों के लिये कैल्शियम और मैग्नीशियम की सीमा से संबंधित अनुपालन की समयसीमा को आगे एक जुलाई तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया है।''

यूपीआई के जरिये लेन-देन पर पहले की तरह कोई शुल्क नहीं लगेगाः एनपीसीआई

नयी दिल्ली। आईपीटी नेटवर्क

नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (एनपीसीआई) ने शुक्रवार को कहा कि यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (यूपीआई) के माध्यम से पैसे भेजना या प्राप्त करना मुफ्त बना रहेगा। एनपीसीआई ने एक बयान में कहा कि एक जनवरी, 2021 से यूपीआई के जरिये पैसा भेजने या प्राप्त करने पर शुल्क लगाये जाने की रिपोर्ट गलत है। फिलहाल, यूपीआई के जरिये लेन-देन पर कोई शुल्क नहीं लगता। एनपीसीआई सुगम और निरंतर यूपीआई लेनदेन की व्यवस्था जारी रखेगी। वर्ष 2008 में गठित एनपीसीआई भारत में खुदरा भुगतान और निपटान प्रणाली के लिये विभिन्न संस्थानों को सुविधा देने वाला संगठन है।

अक्टूबर-दिसंबर में चीनी उत्पादन 42 प्रतिशत बढकर 110.22 लाख टन : इस्मा

नयी दिल्ली। एजेंसी

भारत का चीनी उत्पादन अक्टूबर-दिसंबर के दौरान सालाना आधार पर 42 प्रतिशत बढ़कर 110.22 लाख टन हो गया। व्यापार आंकड़ों में यह जानकारी दी गई है। इसका कारण अधिक गन्ना उत्पादन तथा महाराष्ट्र में चीनी मिलों का जल्दी काम शुरू करना है। चीनी विपणन वर्ष अक्टूबर से सितंबर तक चलता है। भारतीय चीनी मिल संघ (इस्मा) ने एक बयान में कहा कि चीनी मिलों ने वर्ष 2020-21 की अक्टूबर-दिसंबर की अवधि में 110.22 लाख टन चीनी का उत्पादन किया, जबकि पिछले वर्ष की इसी अवधि में 77.63 लाख टन चीनी का उत्पादन हुआ था। महाराष्ट्र में, समीक्षाधीन अवधि में चीनी उत्पादन 39.86 लाख टन रहा, जबकि एक साल पहले समान अवधि में यह 16.50 लाख टन रहा था। उत्तर प्रदेश में चीनी का उत्पादन मामूली वृद्धि के साथ 33.66 लाख टन हो गया जो पिछले साल समान अवधि में 33.16 लाख टन रहा था। अभी तक लगभग 10 लाख टन चीनी निर्यात के संबंध में अनुबंध हो चुके हैं और निर्यात के लिए चीनी को आगे भेजा जाना शुरू हो गया है। सरकार ने चीनी के अधिशेष स्टॉक को खपाने के लिए सितंबर में समाप्त होने वाले विपणन वर्ष 2020-21 के दौरान 60 लाख टन चीनी निर्यात का लक्ष्य तय किया है। इस्मा ने कहा, 'दूसरे सबसे बड़े चीनी निर्यातक देश थाइलैंड में चीनी का उत्पादन, आमतौर पर होने वाली पैदावार से लगभग 80-90 लाख टन कम है। इसलिए, भारत के पास पश्चिम एशिया, श्रीलंका, बांग्लादेश, पूर्व अफ्रीका इत्यादि जैसे अपने पारंपरिक बाजारों के अतिरिक्त विशेषकर इंडोनेशिया और मलेशिया जैसे एशियाई आयात करने वाले देशों को अपनी चीनी का निर्यात करने का अवसर है। इस्मा ने कहा कि भारत के पास मार्च-अप्रैल 2021 तक चीनी निर्यात और उसके लिए अनुबंध करने का अच्छा अवसर है। ब्राजील की चीनी उस समय ही बाजार में आएगी। उद्योग संगठन ने कहा कि पिछले 10 दिनों में रुपये का मूल्य 74 रुपये प्रति डॉलर से सुधरकर 73 रुपये प्रति डॉलर हुआ है जिससे भारतीय रुपये में चीनी मिलों का लाभ काफी हद तक कम हो गया है। इस्मा ने कहा, 'यह मानते हुए कि दुनिया में भारतीय चीनी की मांग है और थाइलैंड, यूरोपीय संघ आदि में चीनी का उत्पादन कम है, भारत वर्ष 2020-21 के दौरान 6,000 रुपये प्रति टन की निर्यात सब्सिडी के समर्थन के साथ अपने लक्षित मात्रा का निर्यात करने में सफल रहेगा।।'

इंदौर में नया अंतरराष्ट्रीय एयर कार्गो टर्मिनल शुरू, मुख्यमंत्री चौहान ने किया लोकार्पण

इंदौर। आईपीटी नेटवर्क

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) की एक सहायक कंपनी ने मध्यप्रदेश से निर्यात को बढ़ावा देने के लिए स्थानीय देवी अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डे पर बुधवार को नया अंतरराष्ट्रीय एयर कार्गो टर्मिनल शुरू किया। इसे एएआई कार्गो लॉजिस्टिक्स एंड अलाइड सर्विसेज (आईक्लास) ने 2.26 करोड़ रुपये की लागत से बनाया है। राज्य के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हवाई अड्डा परिसर में आयोजित कार्यक्रम में इस नये सुविधा केंद्र को लोकार्पित किया। उन्होंने इस मौके पर एक पार्सल को गंतव्य के लिए प्रतीकात्मक रूप से रवाना किया। चौहान ने कार्यक्रम में कहा, ''मध्यप्रदेश भारत का दिल है और यह सूबा भविष्य में देश का बड़ा लॉजिस्टिक्स (माल के परिवहन एवं आपूर्ति का व्यवसाय) केन्द्र बनेगा। इंदौर में अंतरराष्ट्रीय एयर कार्गो टर्मिनल शुरू होने से दवाइयों, चमड़ा उत्पादों, मशीनरी, हीरे-जवाहरात और कलपुर्जों के साथ ही फूलों व फल-सब्जियों के निर्यात को बढ़ावा मिलेगा।' उन्होंने कहा कि बढ़ते हवाई यात्रियों के मद्देनजर इंदौर में हवाई अड्डे का विस्तार जरूरी है। इसके लिए राज्य सरकार भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) को हवाई अड्डे से सटी 22 एकड़ जमीन देगी। मुख्यमंत्री ने इंदौर के लोकसभा सांसद शंकर लालवानी का अनुरोध स्वीकार करते हुए यह भी कहा कि हवाई अड्डे के 20 किलोमीटर की परिधि में लॉजिस्टिक्स सुविधाएं विकसित की जाएंगी। कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी का वीडियो संदेश प्रसारित किया गया। इसमें पुरी ने इंदौर में अंतरराष्ट्रीय एयर कार्गो टर्मिनल के लोकार्पण पर प्रसन्नता जताते हुए कहा कि इस केंद्र से कपड़ों, रेडीमेड परिधानों, दवाओं और खाद्य उत्पादों के निर्यात को बल मिलेगा। अधिकारियों ने बताया कि मध्यप्रदेश की आर्थिक राजधानी कहे जाने वाले इंदौर में 1,330 वर्ग मीटर में फैले अंतरराष्ट्रीय एयर कार्गो टर्मिनल में हर साल 37,960 टन माल का प्रबंधन किया जा सकता है। यह टर्मिनल कोल्ड स्टोरेज के साथ ही अत्याधुनिक एक्स-रे मशीनों और सुरक्षा उपकरणों से लैस है। उन्होंने बताया कि इंदौर से दवाइयों, चमड़ा उत्पादों, मशीनरी, कलपुर्जों, नमकीन-मिठाइयों और अन्य उत्पादों का मुख्यतः संयुक्त अरब अमीरात, बांग्लादेश, हांगकांग, चीन, सिंगापुर, इटली, जर्मनी, फ्रांस और जिम्बाब्वे को निर्यात किया जाता है।

बाजार में 10 दिन की तेजी पर लगा विराम

सेंसेक्स 264 अंक टूटा

मुंबई। एजेंसी

शेयर बाजार में पिछले 10 कारोबारी सत्रों से जारी तेजी पर बुधवार को विराम लग गया और बीएसई सेंसेक्स 264 अंक की गिरावट के साथ बंद हुआ। रिलायंस इंडस्ट्रीज, आईटीसी और इन्फोसिस की अगुवाई में यह गिरावट आई। तीस शेयरों पर आधारित सेंसेक्स कारोबार के दौरान एक समय 48,616.66 अंक तक चला गया था। लेकिन बाद में तेजी बरकरार नहीं रही और यह 263.72 अंक यानी 0.54 प्रतिशत की गिरावट के साथ 48,174.06 अंक पर बंद हुआ। इसी प्रकार, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 53.25 अंक यानी 0.38 प्रतिशत की गिरावट के साथ 14,146.25 अंक पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान एक समय यह 14,244.15 अंक की रेकॉर्ड ऊंचाई तक चला गया था। सेंसेक्स के शेयरों में सर्वाधिक नुकसान आईटीसी को हुआ। इसमें करीब 3 प्रतिशत की गिरावट आई। इसके अलावा जिन प्रमुख शेयरों में गिरावट दर्ज की गयी, उनमें रिलायंस इंडस्ट्रीज, बजाज फाइनेंस, एक्सिस बैंक, एचयूएल और एचसीएल टेक शामिल हैं।

इन शेयरों में गिरावट

दूसरी तरफ जिन शेयरों में गिरावट दर्ज की गयी, उनमें पावर ग्रिड, भारती एयरटेल, ओएनजीसी और अल्ट्राटेक सीमेंट शामिल हैं। रिलायंस सिक्योरिटीज के रणनीतिक मामलों के प्रमुख विनोद मोदी ने कहा कि घरेलू शेयर बाजारों में उतार-चढ़ाव और सुधार का मुख्य कारण जॉर्जिया (अमेरिका) में दो सीनेट सीटों के लिए हुए चुनाव के परिणाम डेमोक्रेट्स के पक्ष में जाना है। उन्होंने कहा, 'सीनेट में डेमोक्रेट्स का नियंत्रण होने से अमेरिका में निम्न कर की दर की स्थिति बदल सकती है। इससे बाजार में कुछ हद तक उतार-चढ़ाव आ सकता है।'

बाकी बाजारों का हाल

कारोबारियों के अनुसार रेकॉर्ड स्तर पर मुनाफावसूली से भी बाजार नीचे आया। एशिया के अन्य बाजारों में शंघाई कंपोजिट सूचकांक और हांगकांग का हैंगसेंग में तेजी रही जबकि जापान में निक्की और दक्षिण कोरिया में कोस्पी नुकसान में रहे। यूरोप में शुरूआती कारोबार में तेजी का रुख रहा। इस बीच, वैश्विक तेल मानक ब्रेंट क्रूड का भाव 0.99 प्रतिशत की बढ़त के साथ 54.13 डॉलर प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा था।

रिलायंस, बीपी का केजी-डी6 से उत्पादन में कमी आने पर खरीदारों को भुगतान का वादा

नई दिल्ली। एजेंसी

रिलायंस इंडस्ट्रीज लि. (आरआईएल) और ब्रिटेन की उसकी भागीदार बीपी पीएलसी ने पूर्वी अपतटीय केजी-डी6 से अगले दौर के उत्पादन में ग्राहकों को तय मात्रा अनुसार प्राकृतिक गैस उपलब्ध नहीं करा पाने की स्थिति में नकद भुगतान की प्रतिबद्धता जतायी है। गैस बिक्री और खरीद समझौता (जीएसपीए) के मसौदे के अनुसार रिलायंस और बीपी ने केजी-डी6 में आर-संकुल से उत्पादित बढ़ी हुई गैस की मात्रा के लिये मूल्य खोज बोलियां साझा की हैं। इसमें साफ कहा गया है कि अगर वे दूसरे दौर के इस उत्पादन में से खरीदार को तय मात्रा में प्राकृतिक गैस की आपूर्ति नहीं कराती हैं, ऐसी स्थिति में विक्रेता वैकल्पिक स्रोत से प्राप्त की गयी गैस के मूल्य के बराबर भुगतान करेगा।

दूसरी तरफ खरीदार कंपनियों को उतनी गैस लेनी होगी जितने को लेकर उन्होंने प्रतिबद्धता जतायी है। ऐसा नहीं करने पर इस्तेमाल नहीं की गई गैस के लिये भुगतान करना होगा। जीएसपीए के अनुसार भुगतान करने के बावजूद गैस की निर्धारित मात्रा अगर नहीं ली जाती है, उसे अगली तिमाहियों में लिया जा सकता है। हालांकि भूकंप, बाढ़, आग लगने, महामारी, युद्ध, हड़ताल, तालाबंदी, सरकारी/नियामकीय कदमों और अदालती आदेश से विलम्ब की स्थिति जैसे आपात हालात में गैस लेने और देने की अनिवार्यता का प्रावधान लागू नहीं होगा।

साथ ही गैस फील्ड क्षेत्रों में नुकसान, विफलता, गतिरोध, उत्पादन या उसकी डिलिवरी को लेकर पाबंदी भी आपात स्थिति की श्रेणी में आएगी। रिलायंस ने एक दशक पहले केजी-डी6 गैस फील्ड से उत्पादित गैस के लिये 6 करोड़ घन मीटर प्रतिदिन गैस बिक्री को लेकर समझौता किया था। लेकिन कुओं से जुड़े मसलों के कारण उत्पादन तेजी से कम हुआ है। इससे बिजली संयंत्र से उपयोगकर्ता पर प्रतिकूल असर पड़ा। कंपनी ने इसके लिये खरीदारों को कोई भुगतान नहीं किया और कहा कि यह चीज उसके नियंत्रण से बाहर है।हालांकि, सरकार ने निर्धारित मात्रा का उत्पादन करने में विफल रहने को लेकर जुर्माना लगाया। इस कदम को कंपनी ने मध्यस्थता न्यायाधिकरण में चुनौती दी। मामले में निर्णय अभी लंबित है। रिलायंस बीपी ने पिछले महीने आर-संकुल क्षेत्रों से उत्पादन शुरू किया। रिलायंस-बीपी ने नवंबर 2019 में केजी-डी6 के आर-श्रृंखला फील्ड से शुरूआती 50 लाख घन मीटर प्रतिदिन (यूनिट) गैस की नीलामी की थी। इसके लिये ब्रेंट क्रूड तेल को आधार बनाया गया। अब दोनों ने बढ़े हुए उत्पादन 75 लाख यूनिट गैस के लिये बोली आमंत्रित की है। यह गैस फरवरी से उपलब्ध होने की संभावना है। रिलायंस और बीपी ने नई बोली में जापान/कोरिया तरलीकृत प्राकृतिक गैस आयात मूल्य के समरूप दर की मांग की है।

रिजर्व बैंक ने मौद्रिक नीति के लिये जानकारियां जुटाने के उद्देश्य से की सर्वे की शुरुआत

मुंबई। एजेंसी

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने मुद्रास्फीति की उम्मीदों और उपभोक्ताओं के विश्वास का पता लगाने के लिये सर्वेक्षण के अगले दौर की शुरुआत की शुक्रवार को घोषणा की। इससे मौद्रिक नीति के लिये उपयोगी जानकारियां मिलती हैं। केंद्रीय बैंक नियमित रूप से ये सर्वेक्षण कराता है। मुद्रास्फीति के प्रत्याशा सर्वेक्षण (आईईएसएच) के जनवरी 2021 के दौर की शुरुआत की घोषणा करते हुए आरबीआई ने कहा कि इसका लक्ष्य 18 शहरों में अपने व्यक्तिगत उपभोग के आधार पर लगभग 6,000 घरों से मूल्य बदलावों और मुद्रास्फीति पर व्यक्तिगत आकलनों का पता लगाना है। इन शहरों में अहमदाबाद, बेंगलुरू, चंडीगढ़, चेन्नई, दिल्ली और तिरुवनंतपुरम शामिल हैं। रिजर्व बैंक ने कहा, ''सर्वेक्षण में तीन महीने में मूल्य में हुए बदलाव (सामान्य मूल्य और विशिष्ट उत्पाद समूहों की कीमतें) के साथ-साथ एक साल आगे की अवधि और मौजूदा अवधि का तुलनात्मक अनुमानित मूल्य पूछा जाता है।'' उपभोक्ता विश्वास सर्वेक्षण (सीसीएस) सामान्य आर्थिक स्थिति, रोजगार परिदृश्य, मूल्य स्तर, परिवारों की आय और व्यय पर उनकी भावनाओं के बारे में गुणात्मक प्रतिक्रियाएं मांगता है। सर्वेक्षण नियमित रूप से 13 शहरों - अहमदाबाद, बेंगलुरू, भोपाल, चेन्नई, दिल्ली, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, पटना और तिरुवनंतपुरम में आयोजित किया जाता है। सर्वेक्षण में 13 शहरों में लगभग 5,400 उत्तरदाताओं को शामिल किया जाता है। आरबीआई ने कहा कि सर्वेक्षण के परिणाम मौद्रिक नीति के लिये उपयोगी जानकारियां प्रदान करते हैं। मौद्रिक नीति समिति की अगली बैठक 3-5 फरवरी 2021 के लिये निर्धारित है।

स्वामी/मुद्रक/प्रकाशक सचिन बंसल द्वारा अपनी दुनिया प्रिंटर्स, 13, प्रेस काम्पलेक्स, ए.बी. रोड, इंदौर से मुद्रित एवं 18, सेक्टर-डी-2, सांवेर रोड, इंडस्ट्रीयल एरिया, जिला इंदौर (म.प्र.) से प्रकाशित। संपादक- सचिन बंसल

सूचना/चेतावनी- इंडियन प्लास्ट टाइम्स अखबार के पूरे या किसी भी भाग का उपयोग, पुनः प्रकाशन, या व्यावसायिक उपयोग बिना संपादक की अनुमति के करना वर्जित है। अखबार में छपे लेख या विज्ञापन का उद्देश्य सूचना और प्रस्तुतिकरण मात्र है। अखबार किसी भी प्रकार के लेख या विज्ञापन से किसी भी संस्थान की सिफारिश या समर्थन नहीं करता है। पाठक किसी भी व्यावसायिक गतिविधि के लिए स्वविवेक से निर्णय करें। किसी भी विवाद की स्थिति में न्याय क्षेत्र इंदौर, मप्र रहेगा।